

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2007.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 मार्च, 2008/28 फाल्गुन, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 14 मार्च, 2008

संख्या वि० स०-लैज-गवर्नमेंट/1-36/2008.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 3) जो आज दिनांक 14 मार्च, 2008 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/—

गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 36—क का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 (1984 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट संक्षिप्त नाम। आचरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

1984 का 3

2. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 धारा 36—क की धारा 36—क के पश्चात्,—
का संशोधन।

(क) निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ परन्तु राज्य सरकार साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण करने या उसमें कोई गिरफ्तारी करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगी।” ; और

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्दों और अंकों “ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21” के स्थान पर “ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग)” शब्द, चिन्ह, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 की धारा 36—क में उपबन्ध है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक सेवक के मामलों में, उप—अधीक्षक पुलिस की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण या कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 का प्रथम परन्तुक यह उपबन्ध करता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य सरकार द्वारा साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा प्राधिकृत है तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 की धारा 36—क के उपबन्धों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और धारा 2 के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अनुकूल लाने के लिए समरूप परन्तुक अन्तः स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि तद्वारा राज्य सरकार को किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों का अन्वेषण करने के लिए साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा प्राधिकृत करने हेतु सशक्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 36—क के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत उपबन्धित “लोक सेवक” की परिभाषा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित “लोक सेवक” की परिभाषा से प्रतिस्थापित करने का भी विनिश्चय किया गया ताकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अपराधों के अन्वेषण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई जा सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री ।

शिमला

तारीख : 2008

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 (1984 का 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री ।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख : 2008

**THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT
PRACTICES (AMENDMENT) BILL, 2008**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 36-A.

**THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT
PRACTICES (AMENDMENT) BILL, 2008**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Prevention of Specific
Corrupt Practices Act, 1983 (Act No.3 of 1984).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Prevention of Short title.
Specific Corrupt Practices (Amendment) Act, 2008.

2. After section 36-A of the Himachal Pradesh Prevention of Amendment
of section
36-A.
Specific Corrupt Practices Act, 1983—
3 of 1984.

(a) the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the State Government may, by general or
specific order, authorize a police officer not below the rank of
Inspector of Police to investigate into, or make any arrest in,
an offence punishable under this Act.”; and

(b) in the Explanation, for the words and figures “section 21 of the
Indian Penal Code”, the words, bracket, letter, figures and
signs “clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption
Act, 1988” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 36-A of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 provides that Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, in the case of a public servant, no police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police shall investigate into, or make any arrest in an offence punishable under this Act, whereas first proviso to section 17 of the Prevention of Corruption Act, 1988 provides that if a police officer not below the rank of an Inspector of Police is authorized by the State Government by general or specific order, he may also investigate any such offence without the orders of the Magistrate of First Class. In order to bring the provisions of section 36-A of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 in consonance with the provisions of section 17 and clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988, it has been decided to insert similar proviso under section 36-A of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, thereby empowering the State Government to authorize by a specific or general order a police officer not below the rank of an Inspector of Police to investigate the cases falling under the Act *ibid*. Further, it has been decided to substitute the definition of “public servant” provided under Explanation to section 36-A of the Act *ibid* with the definition of “public servant” as defined under clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988, so as to bring uniformity in procedure to be followed in investigation of offences under the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :

The _____, 2008.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

**THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT
PRACTICES (AMENDMENT) BILL, 2008**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act,
1983(Act No.3 of 1984).*

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

J. N. BAROWALIA,
Pr. Secretary(Law).

SHIMLA :

The_____, 2008.

